(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों की सेवा अवधि को उनके सेवा निवृत्त होने के बाद बढाया गया और उनमें से प्रत्येक प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि कितनी बार बढाई गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्त होने वाले प्रबन्ध निदेशकों के स्थान पर नई नियुक्तियां करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी और यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) . सरकारी उद्यम चयन मंडल को यह दायित्व सौंपा गया है कि जब कभी प्रशासनिक मंत्रालय प्रबन्ध निदेशकों की सेवा निवृत्ति अधिसूचित करें तो वह उनके उत्तराधिकारियों का चयन करें। अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां कोई विशिष्ट अधिकारी सेवा काल बढाये जाने का सुपात्र हो अथवा उसके स्थान पर सुयोग्य अधिकारी चुनने में विलम्ब अपरिहार्य हो तो कुछ और सेवाकाल बढाना अवश्यम्भावी है । पिछले दो वर्ष के दौरान केवल 4 अधिवर्षिता प्राप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सेवाकाल बढाया गया है । इन अधिकारियों की सेवा अवधि 4 माह, 5 माह, एक वर्ष और दो वर्ष बढाई गई है ।

Violation of Laws by Vimal and Vinod Textile Mills, Ujjain

3962. SHRI NIHAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3143 on 11th March, 1981 regarding violation of laws by Vitmal and Vinod Textile Mills, Ujjain and state :

(a) whether Vimal and Vinod Textile Mills, Ujjain in Madhya Pradesh is facing serious financial crisis and if so, whether and survey report for advancing the loan has been submitted to Government by the Government Financial Institutions;

(b) the amount of loan sought by the company to run the mill and the amount of loan approved by the Government; and

(c) whether any amount of previous loans is oustanding against the company and if so, the amount thereof, financial institution-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b) Binod Mills Co. Ltd. Ujjain comprising of Binod Mills and Bimal Mills is reported to be facing serious financial crisis. The financial institutions have not submitted any survey report to the Union Government for advancing loans to the Company. However, the Company's case was referred by the IDBI for consideration by the Screening Committee on Sick Industries at its meeting held on 24-9-1980 for provision of Rs. 517 lakhs interest free funds by the Central/State Governments to meet statutory dues/overdue creditors. The proposal was rejected by the Screening Committee.

The Company has not made any application for loan to the Union Government nor any loan has been sanctioned by the Government to the Company.

(c) As on 31.3.1981, the outstanding amount of advances of the term lending institutions to the Company was as given below:—

Financial Institutions	Amount Outstanding
	(Rs. in lakhs)
I.D.B.I.	186·81
I.F.C.I.	48·06
M.P.F.C.	20.92
TOTAL :	255·79

विदेशों को टेलीविजन सटों का निर्यात

3963. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय फर्मों के क्या नाम हैं जो विदेशों को टेलिविजन सैटों का निर्यात कर रही हैं और किन किन देशों को कर रही है ; और

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से पोर्टेबल टेलीविजन सेटों का आयात करने की पेशकश की है; और यदि हां, तो कितने मूल्य के सेटों की और किन किन फर्मों के सेट निर्यात किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) मैसर्स वैस्टर्न इलैक्ट्रानिक्स लि०, नई दिल्ली, मैसर्स ओरियण्ट विजन लि०, मद्रास और इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालोजी डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली (ई० टी० टी० डी० सी०) ने नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमरीका को टेलीविजन सेटों का निर्यात किया है ।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को मैसर्स ओपल लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमरीका से उन्हें 12" बी / डब्ल्यू के 2,00,000 टी० वी० सैटों की पूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है । आर्डर का मूल्य 8,474,000 अमरीकी डालर हैं । टेलीविजन सेटों का निर्माण होसुर, तमिलनाडु स्थित मैसर्स ओरियण्ट विजन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा ।

सैशल्ज के लिये विमान सेवा

3964. श्री निहाल सिंह :
आचार्य भगवान देव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैशल्ज के लिए विमान सेवा लागू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत तथा सैशल्ज के बीच विमान सेवा पहले ही मौजूद है तथा किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Norms Fixed by Government to Assist States

3965. **SHRI A. T. PATIL:** Will the Minister of FINANCE be pelased to state:

(a) norms fixed by Government of India, to assist States, when the funds provided as margin money in States' Budgets, on the basis of recommendations of the Seventh Finance Commission, are exhausted and additional expenditure is necessary and incurred by States on natural calamities such as floods, droughts, cyclones, etc.; and

(b) the amount disbursed to the Staes (State-wise) under the aforesaid norms, during the current year and the last four years, together with (i) amounts of margin money provided in the budgets by respective States and (ii) amount of total expenditure incurred by the respective States over and above the margin money, during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) Assistance to States affected by natural calamities is regulated on the basis of the 7th Finance Commission's recommendations, which have been accepted by Government. When a State is affected by a natural calamity and the State Government considers that the expenditure to meet the situation will be more than the margin money or cannot be met from its own resources, it seeks Central assistance by submitting a detailed memorandum. A Central team is deputed to visit the State for an on-the-spot assessment of the damage and for estimating the expenditure to meet the situation. The Report of the Central team is considered by the High Level Committee on Relief. On the recommendations of the Committee, ceilings of expenditure are approved by the Centre for purposes of Central assistance. Central assistance is released to the State Government on the basis of the expenditure reported by it against the approved ceilings and taking into account vailable margin money, in accordance with the recommendations of the 7th Finance Commission.

(b) A statement is laid on the table of the House.